

राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता दिया जाना

10273. श्री लालजी भाई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 13 मार्च, 1979 की "राजस्थान पत्रिका" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह अनुसूचित जाति के बेरोजगार स्नातकों को 150 रु० और स्नातकोत्तरों को 250 रु० मासिक भत्ता देने की अपनी योजना को संशोधित करें ;

(ख) क्या उन्हें सरकारी विभागों में लाभ-प्रद काम देने के लिए 5 लाख 26 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र देहगान) : (क) जी, नहीं । योजना प्रायोग के एक कार्यकारी दल ने राज्य की 1979-80 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करते समय यह सुझाव दिया था कि राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार ग्रेजुएटों और पोस्ट-ग्रेजुएटों को वृत्तिकार्य देने की स्कीम की इस वृष्टि से समीक्षा करनी चाहिए कि वृत्तिकार्यों तथा सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों में प्रशिक्षुता के बीच संबन्धता हो । इस दल ने यह भी सुझाव दिया था कि वृत्तिकार्यों की तुलना में उचित दर की बुकानों, वितरण आदि के जरिए स्व-रोजगार सहित रोजगार उत्पन्न करने की स्कीमों को तरजीह दी जाए ।

(ख) और (ग). "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों को वृत्तिकार्य" नामक स्कीम के लिए 1979-80 में 3 लाख रु० की व्यवस्था है जिस में से 2 लाख रु० अनुसूचित जातियों के लिए और 1 लाख रु० अनुसूचित जनजातियों के लिये है ।

Unauthorised Encroachment by Weaker Sections in Andaman and Nicobar Islands

10274. SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware of about unauthorised encroachments by poor and weaker sections of people in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands; if so, what is the total number of such encroachment colonies, Tehsil-wise and since when;

(b) whether it is a fact that large number of families were evicted in this, if so, what is the policy of the Government in this regard;

(c) whether Government propose to consider such cases for regularising on the similar pattern of Delhi;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) to (e) : The Andaman and Nicobar Administration have reported that about 3325 acres of revenue land in five Tahsils, viz., Port Blair, Ferrargunj, Rangat, Mayabunder and Diglipur in Andaman Islands are under unauthorised encroachment. About 735 acres of encroachments pertain to a period prior to 1961 and about 2590 acres pertain to a later period. In addition, about 2850 acres of forest land in Diglipur, Mayabunder, Rangat, Ferrargunj and Tushanabad Tahsils are also under unauthorised encroachment.

2. Action against those responsible for such encroachments is taken by the Andaman and Nicobar Administration under the provisions of the Andaman and Nicobar Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966 where revenue land is concerned and under the provisions of the Indian Forest Act 1927 if forest land is involved. A number of evictions have been carried out by the Administration in pursuance of these provisions.

3. A decision has been taken that encroachment made prior to 1961 may be regularised by re-allotment of land and the Andaman and Nicobar Administration are taking necessary action in this regard. There is no proposal to regularise the encroachments in Andaman and Nicobar Islands on the lines of those regularised in Delhi as the condition in the two territories are not comparable.

Foreign Collaboration proposals received and approved during 1977 and 1978

10275. SHRI S.R. REDDY :
SHRI GANANATH PRADHAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of foreign collaboration proposals received by Government during the years 1977 and 1978 and number of approvals issued;